territorial waters are within their domain and it is a state subject again. Some of the States have informed us that they are working on the Bills also.

We are also trying to frame a model Bill. It is with the Law Department now. As soon as it is ready, we will send it to the States.

श्रीमती मृणाल गोरे : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बारे में लेजिस्लेशन और माडल बिल बनाया जा रहा है। सरकार ने बड़े बड़े मल्टी-नेशनल्ज को ट्रालर के लिए परवाना दे दिया है, लेकिन वास्तविक परिस्थिति यह है कि ये लोग छोटे फिशरमैन के साथ हमेशा झगड़ा करते हैं। केरल स्टेट ने सजेस्ट किया है कि फिशरीज डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन की तरफ से बड़े ट्रालर्ज लिये जायें। क्या सरकार इस पर विचार कर के सभी स्टेट्स से कहेगी कि बड़े-बड़े मल्टी-नेशनल्ज के द्वारा ट्रालर्ज लेने के बजाये स्टेट्स में फिशरीज डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन के जरिये ट्रालर लिये जायें, ताकि आपस के झगड़े भी कम हो जायें ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह झगड़ा छोटी बोट्स, यानी कनवेन्शनल और नान-मैकेनाइज्ड बोट्स और मेकेनाइज्ड बोट्स का है। बड़े ट्रालर्ज के साथ ऐसा झगड़ा नहीं है। बड़े ट्रालर्ज तो समुन्दर में बीस मील से आगे दूर तक चले जाते हैं। कॉस्टल एरिया में मेनली मैकेनाइज्ड बोट्स और कनवेन्शनल और ट्रेडीशनल बोट्स रांपनकर वगैरह का है।

News Item Captioned "Dream House that Never Was"

\+

*184. DR. BIJOY MONDAL:
SHRI G. M. BANATWALLA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press item appearing in *Hindustan Times* dated the 29th January, 1979 under the heading "Dream House that never was";

(b) the number of plots and flats so far allotted by the DDA since it was set up; and

(c) how much profit DDA have earned so far?

निर्माण और आवास तथा पूर्ती और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :
(क) जी, हां।

(ख) प्लाट—30,245 (रिहायशी)
फ्लैट—35,552 (रिहायशी)

इसके अलावा 59 सहकारी ग्रुप आवास संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया गया है।

(ग) कुछ योजनाओं में, फ्लैटों की लागत में रियायत दी गई है जबकि कुछ अन्य योजनाओं में अतिरिक्त प्रभार लिये गये हैं। तथापि, मूल रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण लाभ कमाने वाला निकाय नहीं है।

DR. BIJOY MONDAL: I would like to know whether it is a fact that DDA acquires land at less than Rs. 8 per square metre from the owners and sells at more than Rs. 100 per square metre, and whether it is also a fact that in some cases these plots are auctioned at exorbitant prices of more than Rs. 500 per square metre. What is the total annual administrative expenditure of the DDA?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): It is correct that the DDA acquires land at a much lesser cost. But about 40 per cent of the land is left for community service and then developmental activities are also undertaken. The cost of these also goes into the cost of the land which is sold to the beneficiaries.

DR. BIJOY MONDAL: I would like to know whether it is a fact that third class materials are used in the construction of flats. I have heard somebody saying that Delhi is a paradise for the contractors. My question is

whether the Government is willing to inquire into this.

SHRI SIKANDAR BAKHT: This is too general a thing for anything to be said. If there is any specific instance, we shall certainly inquire into that.

श्री आर. एन. राकेश : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आबंटन उन्होंने किया है उस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के एम्पलाईज का एवरेज क्या है ?

SHRI SIKANDAR BAKHT: I will require notice for this.

श्री लालजी भाई : मंत्री महोदय ने आंकड़े नहीं बताए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि डी.डी.ए. ने जो फ्लैट एलाट किए हैं उन की प्रति वर्ष संख्या क्या है ? वर्षवार आंकड़े बताएं जिस से मालूम पड़े कि डी.डी.ए. वास्तव में फ्लैट दे रहा है या मैटीरियल की या और किसी तरह की उलझन की वजह से उस की संख्या घट रही है ? वर्षवार संख्या बताएंगे तो उस से वह घटती हुई या बढ़ती हुई नजर आएगी ।

श्री सिकन्दर बख्त : वर्षवार तो मेरे पास इत्तिला नहीं है । नोटिस देंगे तो बता दूंगा । लेकिन इतना बता दूं, सवाल यह था कि जब से डी. डी. ए. शुरू हुआ है तब से कितने मकानात बनाए गए हैं, वह तफसील हमने दे दी है, लेकिन कुछ नयी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिस के मातहत मकानात बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री लालजी भाई : रफ्तार का पता तब चलेगा जब कि वर्षवार आंकड़े बताएंगे । जब तक वर्षवार आंकड़े नहीं बताएंगे तब तक प्रगति मालूम नहीं पड़ेगी ।

श्री सिकन्दर बख्त : मैं अभी बता रहा हूं । अक्सर मैं माननीय सदस्य को परेशान नहीं हूं, वह पूरा जवाब सुनना नहीं चाहते ।

जो पुराना तरीका था और जो रफ्तार थी उस के अन्दर फर्क पैदा होने में थोड़ा वक्त लगना था । टेम्पो अब पकड़ रहा है, तो अब हम तकरीबन 15 सौ मकान हर महीने रिलीज करेंगे । 79-80 से साल भर में 20 हजार मकान बनाने का हमारा प्रोग्राम है ।

Availability and Requirements of Teesta Water

*185. SHRI K. N. DASGUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is the monthly average discharge available in cusecs from the Teesta river in West Bengal near B.G. Railway bridge;

(b) what is the monthly average requirement of Teesta water in cusecs for irrigation purposes in North Bengal districts as suggested in the Project report on Teesta Barrage under construction; and

(c) how many cusecs of Teesta water are demanded by Bangladesh during dry season?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Reliable data regarding water availability are not available. However, the data regarding availability at Anderson Bridge and requirements of India and Bangladesh are given below: